सत्यमेव जयते

श्री रामेश्वर ठाकुर

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधान सभा अधिवेशन

02 फाल्गुन, 1932 शक   भोपाल, सोमवार, 21 फरवरी, 2011

माननीय सदस्यगण,

1. विधान सभा के इस बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

2. मेरी सरकार प्रदेश के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने और उनका जीवन स्तर उठाने के लिये प्रतिबद्ध है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और मध्यप्रदेश राष्ट्र के विकास में सहभागी हो सके, इस भावना को ध्यान में रखते हुये प्रदेश के विकास और जनकल्याण के मूलभूत बिन्दुओं को चिन्हित करने के मंतव्य से मई, 2010 में प्रदेश की विधान सभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया जिसमें संकल्प 2010 पारित किया गया। संकल्प के बिन्दुओं का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3. मेरी सरकार के प्रयासों से इस वर्ष प्रदेश की आर्थिक विकास दर 8.49 प्रतिशत रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार दूसरे वर्ष प्रदेश की विकास दर देश की विकास दर से बेहतर रही है। लेकिन बीते माहों में पाले से फसलों को हुये नुकसान के कारण दु:ख भी है। किन्तु मुझे इस बात का संतोष है कि मेरी सरकार के द्वारा प्रभावित किसानों को पूरी तत्परता से राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने प्रभावित किसानों को तात्कालिक सहायता देने के लिये लगभग 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समुचित राहत प्रदान करने के लिये राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 6—4 में प्रक्रियात्मक संशोधन किये गये हैं तथा राहत राशि की दरें बढ़ायी गईं हैं। पच्चीस प्रतिशत से अधिक फसल क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित खातेदारों की इस वर्ष की भू–राजस्व वसूली माफ की गई है।-प्रभावित किसानों के अल्पावधि कृषि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित किया जाकर इस वर्ष के ब्याज का भुगतान भी मेरी सरकार द्वारा किया जावेगा। साथ ही मध्यावधि ऋण में परिवर्तन के उपरांत प्रभावित किसानों से केवल 3 प्रतिशत की दर से ही ब्याज लिया जायेगा।

4. मेरी सरकार खेती को लाभकारी बनाने के लिये प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं। इस वर्ष अल्पावधि कृषि ऋण की ब्याज दर को कम करके तीन प्रतिशत किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में 36 लाख किसानों को 5 हजार 200 करोड़ रुपये के ऋण वितरित हुए। मेरी सरकार ने अगले वर्ष से किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर कृषि कार्य हेतु अल्पावधि ऋण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से समर्थन मूल्य पर लगभग 35 लाख 39 हजार टन गेहूं की खरीदी की गई। इसके अलावा सहकारी क्षेत्र में सवा आठ लाख क्विंटल बीज के उत्पादन का अनुमान है। इस वर्ष सहकारी क्षेत्र में 20 लाख 64 हजार टन खाद का वितरण किया गया, जो एक कीर्तिमान है।

5. गेहूँ एवं मक्का की नई किस्मों के विकास और अनुसंधान हेतु जबलपुर में बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया की स्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि यंत्रों के निर्माण एवं सुधार के लिये अधोसंरचना के विकास हेतु अप्रैल 2011 से कृषि शक्ति योजना लागू की जा रही है।

6. प्रदेश में उद्यानिकी फसलों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत छिंदवाड़ा में बायो कंट्रोल लैब, बैतूल में टिशू कल्चर लैब, इन्दौर एवं उज्जैन में कोल्ड स्टोरेज तथा बुरहानपुर और बड़वानी में एपिडा की योजना के अंतर्गत केला राईपनिंग चैम्बर स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश में जन-निजी भागीदारी के अन्तर्गत भोपाल, रतलाम एवं हरदा जिलों में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त मण्डीदीप में निजी क्षेत्र में फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है।

7. मेरी सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में पशुओं के इलाज के लिये 40 चिन्हित आदिवासी विकासखण्डों में चल चिकित्सा इकाई स्वीकृत की है। गौ-संवर्द्धन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सागर और रीवा में दुग्ध संघ तथा जबलपुर में डेयरी प्रक्षेत्र की स्थापना की जायेगी।

8. मेरी सरकार ने सड़कों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों के सुधार पर विशेष ध्यान दिया है।

जन-निजी भागीदारी के माध्यम से 7 नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं तथा एशियन बैंक परियोजना के तीसरे चरण में 15 राज्य मार्गों का काम प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही लगभग 177 करोड़ रुपये की लागत से 10 रेलवे ओव्हर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में जन-निजी भागीदारी के अंतर्गत 1150 करोड़ रुपये की लागत से 24 एकीकृत सीमा जांच चौकियों का निर्माण तथा उन्नयन किया जा रहा है। इन चेक-पोस्टों में परिवहन, वाणिज्यिक कर, खनिज, वन इत्यादि विभागों के अधिकारी एक ही स्थल पर बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस वर्ष एक हजार 584 करोड़ रुपये खर्च कर आठ हजार 968 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इस योजना के लिए वर्ष 2010 में मध्यप्रदेश को ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो गाँव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित नहीं हैं, ऐसे लगभग 9 हजार एक सौ गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत तीन वर्षों में लगभग 3300 करोड़ रुपये की लागत से उन्नीस हज़ार 386 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

9. मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई ग्रामीण परिवहन नीति लागू की गई है। इस हेतु ग्रामीण अंचलों में संचालित वाहनों के लिये मोटरयान कर 20 रुपये प्रतिसीट प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

10. मेरी सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इस वर्ष अब तक लगभग 325 लघु सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किया गया है। वर्तमान में 9 वृहद्, 27 मध्यम और 551 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। माही एवं बरियारपुर परियोजनाओं को वर्ष 2011 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत 220 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया गया है। नर्मदा घाटी परियोजनाओं का पूरी तत्परता से क्रियान्वयन किया जा रहा है। नई परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। आदिवासी बहुल मण्डला, डिण्डौरी और अनूपपुर जिलों के लिये प्रस्तावित अपर नर्मदा और हालोन सिंचाई परियोजनाओं का कार्य वर्ष 2011-12 में शुरू किया जायेगा, जिससे 31 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

11. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी जिलों में ''मुख्यमंत्री पेयजल योजना'' लागू की गई है।

12. मेरी सरकार प्रदेश को बिजली के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बल्कि सरप्लस बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिये किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता 8 हजार 596 मेगावाट हो गई है। इसमें केन्द्रीय उपक्रमों का अंश 2 हजार 355 मेगावाट शामिल है। आगामी तीन वर्षों में हमारा लक्ष्य विद्युत उपलब्धता में लगभग 5 हजार मेगावाट की वृद्धि करने का है । मेरी सरकार ने ताप विद्युत् परियोजना की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की एक नीति जारी की है जिसके तहत 50 निजी कम्पनियों द्वारा परियोजना स्थापना के लिये करारनामों पर दस्तखत किये गये हैं। मेरी सरकार ने 4 हजार 150 करोड़ रुपये लागत से फीडर विभक्तिकरण की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया है। इससे वर्ष 2013 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 24 घंटे तथा कृषि कार्यों के लिये 8 घंटे बिजली मिल सकेगी।

किसानों को सस्ती बिजली देने के लिये प्रतिवर्ष लगभग 1400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

13. गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने के लिये पृथक नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई है। राजगढ़ में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है। सौर ऊर्जा आधारित गर्म जल संयंत्र एवं पावर पैक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने विशेष अनुदान की व्यवस्था की है।

14. कुटीर एवं ग्रामोद्योग को मेरी सरकार ने बढ़ावा दिया है। टसर उत्पादन के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें वन विभाग के समन्वय से प्राकृतिक रूप से वनों में उपलब्ध टसर वृक्षों का चिन्हांकन कर 9 हजार 373 हेक्टेयर क्षेत्र में कृमि पालन किया जा रहा है।

15. मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने तथा अधोसंरचना विकास के लिये अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत गत वर्ष तीन हजार 779 करोड़ रुपये से अधिक खर्च

कर दो लाख 41 हजार से अधिक निर्माण कार्य पूरे किये गये तथा 26 करोड़ 23 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। हितग्राहियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिये प्रारंभ की गई मोबाईल बैंकिंग व्यवस्था की सभी ओर सराहना की गई है। जिला अनूपपुर को इस योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इस व्यवस्था को आगामी वर्ष में अन्य जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लगभग अन्ठानवें हजार 735 आवासों का निर्माण हुआ। ग्रामीण आजीविका परियोजना के अन्तर्गत लगभग 94 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर 71 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 86 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस पर गत वर्ष 438 करोड़ रुपये ख़र्च हुए हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 349 करोड़ 55 लाख रुपये के क्रेडिट मोबिलाईजेशन एवं सीसी लिमिट द्वारा 90 हजार 255 स्वरोजगारियों को लाभान्वित किया गया है। बैकवर्ड रीजन ग्राण्ड फण्ड योजना के अंतर्गत 131 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च कर 794 निर्माण कार्य पूरे किये गये।

जलाभिषेक अभियान के अन्तर्गत गत वर्ष एक हजार 450 करोड़ रुपये खर्च कर एक लाख 60 हजार कार्य पूर्ण कराये गये। राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत डीपीएपी में 73 करोड़ 11 लाख रुपये व्यय करके एक लाख 21 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया। जलाभिषेक अभियान के अन्तर्गत इस वर्ष सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य अभिनव पहल के रूप में शुरू किया गया है।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में निजी आवास निर्माण के लिये मुख्यमंत्री आवास मिशन की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत बैंकों से ऋण एवं शासन से अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

17. आर्थिक विकास को गति देने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार औद्योगिक निवेश के लिये देश-विदेश के उद्योगपतियों को आकर्षित करने में सफल रही है। प्रदेश में औद्योगीकरण की गति को बढ़ाने के लिये उद्योग संवर्द्धन नीति-2010 एवं कार्ययोजना जारी की गई है। इस नीति में प्रावधान किया गया है कि स्थापित होने वाले उद्योगों में प्रदेश के मूल निवासियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत रोजगार दिया जाएगा।

एक हजार से अधिक रोजगार देने वाली ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक रोजगार प्रदेश के मूल निवासियों को मिले, उन्हें दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये उद्योग निवेश संवर्धन सहायता संबंधी लाभ एवं प्रवेश कर से मुक्ति की सुविधा देने का भी प्रावधान है। पिछले वर्ष 22 एवं 23 अक्टूबर को खजुराहो में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2 लाख 44 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिये करारनामों पर हस्ताक्षर किये गये। मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अन्तर्गत एक लाख 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश की 58 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कदम उठाये गये हैं। भारत ओमान रिफायनरी, बीना में शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जायेगा। दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के क्रियान्वयन की कार्यवाही चल रही है। इस वर्ष अभी तक 11 हजार से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई। इनमें 23 हजार से ज्यादा लोगों को काम मिला है।

18. खनिज संपदा के प्रदेश में ही मूल्य संवर्धन और खनिज क्षेत्र में नये निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई खनिज नीति बनायी गई है।

19. मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। अगले शिक्षा सत्र से बालिकाओं के साथ ही बालकों को भी साईकिल और गणवेश देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 341 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में तथा 70 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है। इसके अलावा 201 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं।

सभी बसाहटों के समीप प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने 378 नई प्राथमिक शालाओं एवं 920 नई माध्यमिक शालाओं को खोलने का निर्णय लिया है। शासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में अधोसंरचना के विकास हेतु वर्ष 2010-11 में निर्माण कार्यों के लिये रुपये एक हजार 606 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण कार्यक्रम एवं सक्रिय अधिगम प्रणाली के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, अतः आगामी शैक्षणिक सत्र में इनका विस्तार किया जायेगा। शिक्षक कल्याण एवं प्रबंधन के लिए सभी शिक्षकों की ई-सेवा पुस्तिकाएं तैयार की जा रही हैं। अभी तक तीन लाख से अधिक ई-सेवा पुस्तिकाएं तैयार की जा चुकी हैं।

20. प्रतिभावान छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहन हेतु शुरू की गई गांव की बेटी योजना एवं प्रतिभा किरण योजना के तहत इस वर्ष 34 हजार 504 मेधावी बेटियों को 18 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई। कम आमदनी वाले परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये बैंक कर्ज आसानी से मिल सके, इसके लिये उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है। कक्षा बारहवीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है।

21. मेरी सरकार ने तकनीकी शिक्षा के महत्व को देखते हुए इसे उच्च प्राथमिकता में रखा है। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाकर उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन के तहत् मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की गई है। कौशल विकास के अवसरों में वृद्धि के लिए प्रदेश में आईटीआई एवं कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और इसमें गुणात्मक सुधार को भी बढ़ावा दिया है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिये जबलपुर में चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

22. अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये ठोस प्रयास किये गये हैं। इस वर्ष बालकों की शिष्यवृत्ति दर 500 रुपये से बढ़ाकर 675 रुपये प्रतिमाह तथा बालिकाओं की शिष्यवृत्ति दर 525 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये प्रतिमाह की गई है। आने वाले तीन वर्षों में प्रत्येक आदिवासी विकासखण्ड में अंग्रेजी माध्यम से आश्रम शाला संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष 20 विकासखण्डों में आश्रम शालाएं शुरू की गई हैं तथा 163 छात्रावासों को 50 सीटर बनाया गया है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये इस वर्ष चार नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोले गये हैं तथा प्री-मैट्रिक छात्रावासों में एक हजार से अधिक सीटों की वृद्धि की गई है।

23. विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जातियों के लिये विकास अभिकरण गठित है, जिसके माध्यम से इन वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु 6 करोड़ 36 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन जातियों के लिए पृथक् से विभाग का गठन किया जा रहा है।

24. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। मेरी सरकार का संकल्प है कि एक भी पात्र वन निवासी इसके लाभ से वंचित न रहे। दो अक्टूबर 2010 से आयोजित ग्राम सभाओं में पूरे प्रदेश में दावा लगाने से वंचित रहे वन निवासियों को दावा लगाने का एक और अवसर प्रदान किया गया। प्रदेश में अब तक एक लाख 43 हजार से भी अधिक दावेदारों के अधिकार मान्य कर लिये गये हैं।

25. पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण पर भी मेरी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के कार्य में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी रहा है। प्रदेश के प्रयासों की प्रशंसा विशिष्ट तौर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

इस वर्ष पहली बार भोपाल से सीधे जेद्दाह उड़ान की ऐतिहासिक शुरूआत की गई है। इस वर्ष लगभग 15 हजार वक्फ संपत्तियों का कम्प्यूटराईजेशन प्रारंभ किया गया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला भोपाल के लिये रुपये 15 करोड़ की राशि कन्या छात्रावास, एक हजार इंदिरा आवास एवं आंगनबाड़ी भवन आदि हेतु पहली बार स्वीकृत की गई है। आगामी तीन वर्षों में 50 जिलों में 100 सीटर पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।

26. मेरी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास पर पूरा ध्यान दिया है। कन्या जन्म और बालिकाओं के प्रति समाज के नजरिये में सकारात्मक बदलाव लाने के लिये शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 6 लाख 29 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत अब तक एक लाख 40 हजार से अधिक कन्याओं के विवाह कराये जा चुके हैं।

27. मेरी सरकार ने प्रदेश में सभी वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस काम किया है। प्रदेश में संस्थागत प्रसव बढ़कर अब 81 प्रतिशत हो गया है जिससे शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करने में मदद मिली है। शिशु मृत्यु दर कम करने के लिये 21 जिला चिकित्सालयों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई स्थापित की गई है। आयुष सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिये 148 नवीन आयुष औषधालय शुरू किये जा रहे हैं। बच्चों में कुपोषण दूर करने के प्रभावी प्रयास के उद्देश्य से अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन शुरू किया गया है। प्रदेश में पांच वर्ष तक आयु के गंभीर कुपोषण से प्रभावित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्रों में रखकर उपयुक्त प्रबंधन किया जाता है। प्रदेश में ऐसे 234 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं।

28. वनों में तथा वनों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों, विशेषकर आदिवासियों के लिये महुआ अत्यंत उपयोगी प्रजाति है। प्रदेश में वर्ष 2011 को महुआ वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और इस दौरान 20 लाख महुआ पौधों का रोपण किया जायेगा।

बांस रोपण हितग्राहीमूलक योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 63 हज़ार 468 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वनवासियों को अचार गुठली एवं लाख का उचित मूल्य दिलाने के लिये इन दोनों वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण दर को 550 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है, जिसके फलस्वरूप लगभग 32 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 130 करोड़ रुपये से अधिक पारिश्रमिक के रूप में मिला है। धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है।

29. मेरी सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास पर यथोचित ध्यान दिया है। शहरों के व्यवस्थित विकास के लिये वर्ष 2013 तक सभी शहरों के सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जायेंगे। अभी तक 106 शहरों के प्लान तैयारी के अंतिम चरण में है। इन्दौर तथा भोपाल महानगरों में यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिये दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को मेट्रो रेल की साध्यता सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत इन्दौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन शहरों के सुनियोजित विकास के लिये तीन हजार 348 करोड़ रुपये की लागत से 49 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

इसके साथ ही शहरी गरीबों के लिये 60 हजार से अधिक आवास बनाये जा रहे हैं।

30. खजुराहो एवं महेश्वर-मण्डलेश्वर में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा अमरकंटक, कटनी, सिंगरौली और रतलाम में विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। पचमढ़ी एवं अमरकंटक स्थित जैव मण्डलीय संरक्षित क्षेत्र में संरक्षण कार्यक्रम तीव्र गति से किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी, होशंगाबाद, बीहर नदी, रीवा एवं मंदाकिनी नदी, चित्रकूट तथा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत सागर एवं शिवपुरी तालाबों के संरक्षण एवं उन्नयन का कार्य चल रहा है।

31. मेरी सरकार ने कृषि मजदूरों, निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों, हम्मालों, तुलावटियों, रिक्शा चालकों, हाथ ठेला चालकों तथा घरों में काम करने वाली बहनों के सामाजिक संरक्षण के लिये कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं जिनकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। इन योजनाओं में पंजीकृत हितग्राहियों और उनके परिजनों को विवाह सहायता, प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति सहायता, बीमारी सहायता तथा दुर्घटना अथवा मृत्यु की दशा में सहायता प्रदान की जा रही है।

अब इस व्यवस्था को और प्रभावी तथा परिणाममूलक बनाने के उद्देश्य से इनका एकीकरण कर समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मध्यप्रदेश भवन एवं संन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दो लाख 13 हजार श्रमिकों का पंजीयन किया गया है और एक लाख 54 हजार 335 श्रमिकों और उनके परिजनों को लगभग रुपये 30 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत लगभग 14 लाख 98 हजार भूमिहीन खेतिहर ग्रामीण मजदूरों का पंजीयन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में एक लाख से अधिक मजदूरों को रुपये 34 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

32. समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासकीय योजनाओं का लाभ ज्यादा आसानी से पहुंचाने के प्रति मेरी सरकार संकल्पित है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में प्रत्येक जिले में अंत्योदय मेलों के आयोजन की शुरुआत की गई है। इन मेलों में विभिन्न योजनाओं के तहत् लाखों गरीब परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगमता से दिया जा रहा है।

33. मेरी सरकार ने प्रदेश में संस्कृति और कलाओं के संरक्षण और संवर्धन को विशेष महत्व दिया है। विभिन्न तीर्थों एवं मेलों के सुनियोजित प्रबंधन के लिये तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। राजाभोज के राज्यारोहण के एक हजार वर्ष पूरे होने के अवसर पर कई समारोह आयोजित किये जायेंगे। भोपाल के बड़े तालाब में राजाभोज की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। चित्रकूट में लीला गुरुकुल तथा भोपाल में वाकणकर सृजनपीठ की स्थापना की पहल की गयी है।

34. प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को निरन्तर बढ़ावा दिया जा रहा है तथा अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। बारह सौ व्यक्तियों की क्षमता का वृहद कनवेन्शन सेन्टर, भोपाल में स्वीकृत किया गया है।

35. मेरी सरकार द्वारा खेल एवं युवा कल्याण की दिशा में किये गये ठोस प्रयासों के फलस्वरूप महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मध्यप्रदेश को "राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2010" से सम्मानित किया गया है। पिछले वर्ष हमारे खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 22 एवं राष्ट्रीय स्तर के 281 पदक प्राप्त हुए।

36. मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति लगातार बेहतर बनी हुई है। पुलिस बल में रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है तथा भूतपूर्व सैनिकों की एक विशेष सहयोगी वाहिनी के गठन का निर्णय लिया है। प्रदेश के 75 थानों में 6 हजार 200 पदों की स्वीकृति जारी की गई है तथा महिला डेस्क की स्थापना के लिये द्वितीय चरण में 329 नवीन पद स्वीकृत किये गये हैं। इसके साथ ही इस वर्ष सहायक लोक अभियोजन अधिकारियों के कुल 682 अतिरिक्त नये पद सृजित किये गये हैं। अनुसूचित जाति कल्याण विशेष थानों में पंजीबद्ध अपराधों के अनुसंधान के लिये 45 जिलों में उप पुलिस अधीक्षक अजाक की पदस्थापना की गई है। पुलिस कर्मियों के एक हजार 115 आवास गृहों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में किया गया है।

37. मेरी सरकार ने जेलों को सुधारगृह के रूप में बदलने के लिये सुविचारित प्रयास किये हैं। बंदियों में अनुशासन तथा जवाबदार नागरिक की भावना विकसित करने के लिये होशंगाबाद में नवजीवन आश्रम (ओपन जेल कॉलोनी) का निर्माण किया गया है। इस आश्रम में बंदियों को अपने परिवार के साथ रहने की सुविधा दी गई है।

38. मेरी सरकार प्रदेश में सुशासन देने के लिये प्रतिबद्ध है। शासकीय कार्यालयों में साप्ताहिक जनसुनवाई की व्यवस्था से नागरिकों की समस्याओं के समाधान में बहुत मदद मिली है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, त्वरितता एवं दक्षता बढ़ी है। प्रदेश में स्टेट डाटा सेन्टर स्थापित किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किये गये विशिष्ट प्रयासों का परिणाम है कि 13वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स पुरस्कार-2010 में कुल 6 श्रेणियों में से मध्यप्रदेश की परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में गोल्डन आइकॉन तथा एक सिल्वर आइकॉन अवार्ड्स प्राप्त हुए।

39. शासकीय योजनाओं का समय पर और सही लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिले इसी में लोकतंत्र की सार्थकता निहित है। मुझे यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार ने आम लोगों को लोक सेवाएं समय-सीमा में प्रदान करने के लिये लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम लागू किया है तथा इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पृथक से लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक को सेवा प्रदाय न करने अथवा विलंब करने की स्थिति में जुर्माने तथा प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।

यह काफी उत्साहजनक है कि कानून लागू करने के चार महीने की अवधि में ही लगभग 19 लाख 42 हजार आवेदनों पर समय-सीमा में लोक सेवाएं प्रदान की गई हैं।

40. भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के प्रति अपने दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुये मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के शीघ्रता से निराकरण के लिये विशेष न्यायालय के गठन तथा लोक सेवकों द्वारा भ्रष्ट तरीके से अर्जित सम्पत्ति को राजसात करने के लिये कानून बनाने का निर्णय लिया है।

41. मुझे पूरा विश्वास है कि समावेशी विकास की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए मध्यप्रदेश शीघ्र ही देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

जय हिन्द।